सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार

2029. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों/संगठनों में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और कितने अधिकारियों को सेवा से निकाल दिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भ्रष्टाचार और कदाचार के मामलों में केवल स्थानान्तरण की सजा दी गई है ; और

(घ) भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय (भारी ऊद्योग विभाग में) राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) जहां तक सार्वजनकि क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडलों में शामिल अधिकारियों का सम्बन्ध है, दो अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण, पिछले 3 वर्षों में किसी भी अधिकारी को सेवा से हटाया नहीं गया है।

(ग) जी, नही।

(घ) सार्वजनकि क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं ताकि वे अपने संगठनों में सतर्कता-कार्य कर सकें। सार्वजनकि क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु तैयार की गई कार्य योजनाओं को गहन रूप से मानीटर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच सम्बद्ध अभिकरणों के परामर्श से की जाती है।

Incentives to small scale industries

2030. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to start special incentives scheme for small scale and tiny units in the country; and

(b) if so, the details thereof indicating therein the progress, if any, made by the States in implementing the scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES) (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) In pursuance of policy measures for promoting and strengthening small, tiny and village enterprises announced on 6th August, 1991, a scheme of Integrated Infrastructural Development (including Technological back-up services) for small scale industries in rural/backward areas is under finalisation.

Package Scheme of 1988

2031. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the benefits given by Government to eligible entrepreneurs under the "Package Scheme 1988"; and

(b) the number of applications pending under the scheme and the time likely to be taken for their clearance?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) In order to accelerate the industrial growth and give a strong impetus to

the industrialisation of backward areas, a package of delicensing of industries was announced by the Government on 3rd June, 1988. This scheme exempted the industrial undertakings from the licensing provisions subject to certain investment limits, locational criteria, import content of raw-materials and the compulsory licensing list. The scheme is no longer relevant in the wage of the New Industrial Policy, July, 1991. There are no pending proposals under this scheme.

Contract between BBUNL and Essar India Ltd.

2032. PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd., entered into a contract with Essar India Ltd., a private concern for supply of 'Jongs' from Jessop's Works at a reduced rate;

(b) whether the contract was entered into without obtaining the recommendation of the Director (Finance), as is required under the rules;

(c) whether the then Director (Production) was released from the services of Jessop & Co. Ltd. so as not to reveal the irregularity in this contract; and

(d) fi so, what acton has been taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) M/s. Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd. (BBUNL) have not entered into any contract with Essar India Limited. However, Jessop & Company Limited, a subsidiary of Bharat Bhari Udyog Nigam Limited entered into a contract with Essar Steel which is a division of Essar Gujarat Limited for supply of a package of bridge for cranes including Tongs and electrical drives at competitive price. No separate contract was entered into for supply of Tongs. The contract was approved by Director (Finance) and Managing Director, Jessop & Company Limited.

(c) and (d) The person who was then Director (Production) of Jessop and Company Lmited continues to be the Director (Production) even now.

गुजरात में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

2033. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में केन्द्रीय सरकार के किन-किन सार्वजनकि क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की कमी हुई है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप इन उपक्रमों की कार्यकुशलता और लाभ में वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन उपक्रमों की कार्य कुशलता और लाभ को और अधिक बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 31 मार्च, 1992 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे दो उद्यम नामश: इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स लि० और नेशनल टेक्सटाईल कारपो० (गुजरात) लि० थे जिनके पंजीकृत कार्यालय गुजरात में थे । पिछले तीन वर्षों के दौरान सकल परिसम्पत्ति के रूप में या ऋणों